15 लाख स्वीकृत पदों में से 2.87 लाख रिक्त हैं रेलवे में। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में रेलमंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी।

कमलनाथ सरकार अल्पमत में, राज्यपाल कराएं फ्लोर टेस्ट : भाजपा

सियासी उठापटक ▶ भाजपा नेताओं ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर की मांग, राज्यपाल ने मुख्य सचिव व डीजीपी को तलब किया

भाजपा नेताओं ने कहा- 16 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले विशेष सत्र बुलाएं

राज्य ब्यूरो, भोपाल

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर पिछले 13 दिन से छाए संकट के निर्णायक हल का वक्त आ गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर कहा कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में है, इसलिए सरकार को निर्देश दें कि वह फ्लोर टेस्ट कराए। राजभवन विधि विशेषज्ञों को बुलाकर कानूनी संभावनाओं को टटोल रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। इन नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए अब संवैधानिक ढंग से सरकार चलाना संभव नहीं है, इसलिए 16 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले विशेष सत्र बुलाकर सरकार को केवल फ्लोर टेस्ट करने को कहा जाए। इसके बाद राजभवन की गहमागहमी बढ़ गई। राज्यपाल ने प्रदेश के मुख्य सचिव एसआर मोहंती और पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी को तलब कर कानून व्यवस्था और बेंगलुरु से आने वाले विधायकों की सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर फीडबैक हासिल किया।

फ्लोर टेस्ट का निर्देश देना राज्यपाल का संवैधानिक विशेषाधिकार : कानून के जानकार कहते हैं कि जब राज्यपाल को संदेह हो जाए कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वह फ्लोर टेस्ट का निर्देश दे सकता है। वह भी तब, जबकि राज्यपाल इससे संतुष्ट हो जाएं कि वाकई संवैधानिक संकट की स्थिति बन गई है, सरकार बहुमत खो चुकी है।

फ्लोर टेस्ट पर किसकी-क्या राय

- मौजूदा हालात में राज्यपाल को संवैधानिक अधिकार है कि वह सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि संवैधानिक संकट की स्थिति में फ्लोर टेस्ट का निर्देश देना राज्यपाल का विशेषाधिकार है। कर्नाटक और उत्तरप्रदेश मामले का निर्णय इसका उदाहरण है।
  - रविनंदन सिंह, सीनियर एडवोकेट, पूर्व महाधिवक्ता, मप्र
- किसी भी सरकार के पास बहुमत होने या न होने का फैसला सदन में ही हो सकता है। राज्यपाल को यदि संदेह है तो वे सरकार को विश्वास मत हासिल करने की सलाह दे सकते हैं।
  - अनूप मिश्रा, पूर्व महासचिव, लोकसभा सचिवालय
- संवैधानिक प्रावधान यह है कि विधानसभा का सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से ही शुरू हो। उसके बाद सदन की किसी भी कार्यवाही को वैधता मिलती है। अभिभाषण से ही सत्र शुरू माना जाता है, उसके बाद ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अथवा अन्य कोई कार्यवाही मान्य होगी।
  - सुभाष कश्यप, संविधान विशेषज्ञ
- हाई कोर्ट के निर्णय में भी यही बात कही गई बिना अभिभाषण के विधानसभा की कार्यवाही अवैधानिक मानी जाएगी। हाईकोर्ट का निर्णय भी यही कहता है।
  - भगवान देव ईसराणी, मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव

भोपाल में शनिवार को भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर विधानसभा में शक्ति परीक्षण (फ्लोर टेस्ट) कराने की मांग की। प्रेट्र

छह बर्खास्त मंत्रियों के विधानसभा से इस्तीफे मंजूर

- स्पीकर प्रजापति ने नियम विरुद्ध आचरण पर की कार्रवाई
- दूसरे दिन भी बेंगलुरु से नहीं आए बागी विधायक, स्पीकर करते रहे इंतजार

राज्य ब्यूरो, भोपाल

मप्र के विधानसभा के स्पीकर नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने शनिवार शाम को कमलनाथ सरकार के छह बर्खास्त मंत्रियों के विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे मंजूर कर लिए। स्पीकर ने इन्हें लगातार दूसरे दिन शनिवार को बुलाया था, लेकिन छहों पूर्व मंत्री और सात अन्य बागी विधायक भोपाल नहीं पहुंचे। नियम विरुद्ध आचरण पर स्पीकर ने यह कार्रवाई की।

मालूम हो कि राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की सिफारिश पर शुक्रवार को ही इन छह मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था। सिंधिया समर्थक 19 बागी विधायक पिछले छह दिनों से बेंगलुरु में डेरा डाले हुए हैं। इन सभी ने वहीं से भाजपा नेताओं के जरिए अपने इस्तीफे स्पीकर को भेज दिए थे। कोई फैसला लेने से पहले स्पीकर ने इन विधायकों को प्रत्यक्ष रूप पेश होने का आदेश दिया था। शनिवार को छह पूर्व मंत्रियों और सात विधायकों को पेश होना था। स्पीकर पूरे दिन इंतजार करते रहे, लेकिन वे नहीं आए।

स्पीकर ने शनिवार को सात विधायकों हरदीप सिंह डंग, बृजेंद्र सिंह यादव, रघुराज सिंह कंषाना, गिर्राज डंडौतिया, मुन्नलाल गोयल, ओपीएस भदौरिया तथा राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को बुलाया था।

छह पूर्व मंत्रियों को दूसरी बार मौका दिया था : स्पीकर ने शुक्रवार को छह बागी मंत्रियों (अब बर्खास्त)-तुलसीराम सिलावट, इमरती देवी, गोविंद सिंह राजपूत, डॉ. प्रभुराम चौधरी, प्रद्युम्न सिंह तोमर और महेंद्र सिंह सिसौदिया को नोटिस देकर बुलाया था और वे नहीं आए थे तो शनिवार को दूसरी बार बुलाया गया था।

रंगपंचमी होने के बाद भी इस्तीफा देने वाले सात विधायकों को प्रत्यक्ष रूप से बुलाया था और उनका इंतजार किया। जिन छह मंत्रियों को शुक्रवार को बुलाया था और वे नहीं आए थे, उन्हें भी एक और मौका दिया था। मगर शाम तक कोई नहीं आया। रविवार को भी नौ विधायकों को बुलाया है।

- नर्मदा प्रसाद प्रजापति, अध्यक्ष, मप्र विधानसभा

जयपुर में डेरा डाले विधायक बोले, कमलनाथ सरकार सुरक्षित

जागरण संवाददाता, जयपुर

पिछले तीन दिन से यहां डेरा डाले मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों का दावा है कि कमलनाथ सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। इस बीच, इन विधायकों का धार्मिक पयर्टन जारी है। शनिवार को इन्होंने मेंहदीपुर बालाजी के दर्शन किए। देर शाम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इनसे मुलाकात की।

जानकारी के मुताबिक इन विधायकों में 44 को ब्यूना बिस्टा रिसॉर्ट और 39 को ट्री हाउस रिसॉर्ट में ठहराया गया है। इन्होंने शुक्रवार को खाटूश्याम जी और सालासर हनुमान जी मंदिर के दर्शन किए थे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेंद्र बघेल का कहना है कि धार्मिक स्थलों में पूजा-अर्चना कर उन्होंने कमलनाथ सरकार के फ्लोर टेस्ट में सफल होने की कामना की। विधायक संजय शुक्ल ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि सभी विधायक एकजुट हैं और कमलनाथ सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में रह रहे विधायक हमारे साथ हैं। उन्हें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में भेजने के लिए दबाव बनाने की बात कह कर वहां ले जाया गया है। रविवार को मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होने के लिए मंत्री भोपाल जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये विधायक रविवार शाम अथवा सोमवार सुबह भोपाल जाएंगे। कुछ विधायकों की मुख्यमंत्री कमलनाथ से मोबाइल पर बात हुई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इन विधायकों के साथ ठहरे हुए हैं। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित एक दर्जन नेता इनकी आवभगत में लगे हैं। दोनों रिसॉर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। करीब आधा किमी दूर से ही आने-जाने वालों की जांच की जा रही है। मनोरंजन के लिएकार्यक्रम हो रहे हैं।

गुजरात के विधायक भी आएंगे : राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही उठापटक के बीच गुजरात के कांग्रेस विधायक शनिवार देर रात अथवा रविवार सुबह जयपुर आएंगे। गुजरात में राज्यसभा की चार सीटों के लिए भाजपा के तीन और कांग्रेस के दो प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। क्रॉस वोटिंग के भय से कांग्रेस एक दर्जन विधायकों को जयपुर लाने की तैयारी कर रही है। इनको भी ब्यूना बिस्टा रिसॉर्ट में ठहराया जाएगा।

जयपुर स्थित ब्यूना बिस्टा रिसॉर्ट में ठहराए गए मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों से शनिवार को मिलने पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जागरण

कांग्रेस के 14 विधायक जयपुर रवाना

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद : राज्यसभा चुनाव में क्रास वोटिंग से बचने के लिए गुजरात कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर भेजना शुरू किया है। शनिवार को 14 विधायक भेज दिए गए और दूसरा जत्था रविवार को जाएगा। पार्टी करीब 50 विधायकों को राजस्थान भेजेगी। गुजरात से राज्यसभा की चार सीटों के लिए पांच उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए 26 मार्च को चुनाव से ही जीत हार तय होगी। कांग्रेस के 14 विधायक शनिवार शाम को इंडिगो के विमान से जयपुर रवाना हुए। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से कच्छ के विधायक प्रद्युम्न सिंह उनके साथ नहीं गए। उन्होंने दो-तीन बार मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के कामों की प्रशंसा की थी, इसलिए उनको लेकर शंका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया का कहना है कि भाजपा लालच व भय दिखाकर कांग्रेस विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। अगस्त 2017 में भी भाजपा ने ऐसा ही प्रयास किया था।

सिद्धू ने तोड़ा अज्ञातवास, यूट्यूब चैनल के जरिए जीतेंगे लोगों का विश्वास

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

नौ महीनों से सत्ता के गलियारों से गायब क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू अब यू-ट्यूब के जरिए राजनीतिक उड़ान भरेंगे। अपना अज्ञातवास तोड़ते हुए उन्होंने यूट्यूब पर 'जीतेगा पंजाब' चैनल शुरू किया है जिसके जरिए लोगों से रूबरू होंगे। शनिवार को प्रेस बयान जारी कर उन्होंने इसकी जानकारी दी है। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और यह माना जा रहा है कि सिद्धू अभी से उसकी तैयारियों में जुट गए हैं।

चार मिनट का एक वीडियो डालकर पंजाब के पूर्व मंत्री सिद्धू ने बताया है कि यूट्यूब चैनल के जरिए वह विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे और पंजाब के लोगों की नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे। समान विचारधारा वाले लोगों को अपने इस चैनल पर आमंत्रित करेंगे और उनके साथ इंटरव्यू और विचार-विमर्श के जरिए पंजाब के मुद्दों व समस्याओं के समाधान की कोशिश करेंगे। सिद्धू ने कहा है कि नौ महीनों में उन्होंने जो चिंतन-मनन किया है उससे एक बात सामने आई है कि पंजाब के मुद्दों पर न केवल अपनी बात रखनी होगी, बल्कि एक रोडमैप भी तैयार करना होगा।

सवाल यह है कि उन्होंने आखिर यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों की नब्ज पकड़ने का रास्ता क्यों अपनाया है? जैसा कि उनके वीडियो से साफ जाहिर है कि उन्हें यह अंदेशा है कि उनकी बातों को अक्सर तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है। इसलिए उन्होंने सीधा यह रास्ता अपनाया है। सिद्धू सरकार में रहकर भी शराब माफिया, रेत माफिया आदि पर लगाम कसने की बात करते रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। अब वह इन मुद्दों पर जनता की राय को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे ताकि जब चुनाव नजदीक आएं तो वह अपने लिए कोई बड़ा फैसला ले सकें। कुल मिलाकर वह बड़ी चुनौती स्वीकार करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं।

गुरु ने ठोकी ताली

- नवजोत सिंह सिद्धू ने शुरू किया 'जीतेगा पंजाब' चैनल, जानेंगे जनता की नब्ज
- विधानसभा चुनाव से दो साल पहले ही तैयारी में जुटे

कैप्टन से मतभेद के बाद दिया था इस्तीफा : मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मतभेद पैदा होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने पार्टी व मीडिया से दूरी बना ली थी। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात की थी, लेकिन अपने अज्ञातवास के बारे में बात करने से इन्कार कर दिया था। बीते माह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद केवल इतना कहा था कि वह उन्हें पंजाब की स्थिति से अवगत करवाकर आए हैं।

आप में जाने की चली थी चर्चा : सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की भी चर्चा चली थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। आप के नए पंजाब प्रभारी जरनैल सिंह ने कहा था कि सिद्धू को आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए।

पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में छह रुपये प्रति लीटर की हो चुकी कमी

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

मौजूदा राजकोषीय स्थिति को देखते हुए इसकी जरुरत है। जनवरी के दूसरे हफ्ते के बाद से पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में छह रुपये प्रति लीटर की कमी हो चुकी है। वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी में सरकारी तेल कंपनियों ने विदेशी बाजारों से 66 डॉलर प्रति बैरल (159 लीटर) की दर से क्रूड की खरीद की थी। मार्च में यह गिरकर 32 डॉलर प्रति बैरल रह गई है। इसकी वजह से इस वर्ष 11 जनवरी को दिल्ली में पेट्रोल की जो कीमत 76.01 रुपये प्रति लीटर थी, वह 14 मार्च को घाटकर 69.87 रुपये प्रति लीटर रह गई। दौरान डीजल 69.17 रुपये प्रति लीटर से घटकर 62.68 रुपये प्रति लीटर हो गई है। सनद रहे कि पेट्रो उत्पादों से राजस्व संग्रह सरकार के कुल संग्रह में काफी अहम हिस्सा देता है। वर्ष 2014-15 में इन उत्पादों से सरकार को 99 हजार करोड़ का राजस्व मिला था जो वर्ष 2016-17 में बढ़ कर 2.42 लाख करोड़ रुपये हो गया।

पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाने के खिलाफ हमलावर हुई कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

निशाने पर सरकार

- कच्चे तेल के दाम में गिरावट का फायदा आम लोगों को नहीं देने को बताया जनविरोधी
- पेट्रोल-डीजल के दाम 40 फीसद घटाने की मांग पर संसद में सरकार को घेरेगी पार्टी

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी गिरावट का फायदा आमलोगों को नहीं देने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने उत्पाद शुल्क बढ़ाने को सरकार की मनमानी करार देते हुए तत्काल पेट्रोल-डीजल के साथ रसोई गैस की कीमतें घटाने की भी मांग की है। साथ ही यह भी एलान किया है कि आम जनता को फायदा देने के बजाय टैक्स बढ़ाकर सरकारी खजाना भरने के मुद्दे को पार्टी संसद के मौजूदा सत्र में पार्टी जोर-शोर से उठाएगी।

पेट्रोल-डीजल पर तीन रुपये प्रति लीटर की दर से उत्पाद शुल्क बढ़ाने के फैसले का विरोध करते हुए कांग्रेस ने यह एलान किया। पार्टी प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि कच्चे तेल का दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2004 के स्तर पर पहुंच गया है। इसीलिए पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम कम-से-कम 40 फीसद घटाए जाने चाहिए, ताकि फायदा आमलोगों को मिले, क्योंकि सरकार ने इसी दलील के साथ तेल की कीमतों को बाजार से लिंक किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कच्चे तेल के दाम में बड़ी गिरावट का फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है, तो फिर मार्केट लिंक नीति का मतलब क्या रह गया है?

माकन ने कहा कि राजग के करीब छह साल के शासन में अधिकांश समय कच्चे तेल की कीमतें काफी कम रही हैं। लेकिन इसका फायदा आमलोगों को देने के बजाय बार-बार टैक्स बढ़ाकर सरकार ने अपनी तिजोरी भरी है। कीमतों में मौजूदा गिरावट के चलते 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त फायदा तो सरकार को केवल अभी होगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य डॉ. नीलेश शाह का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को एक साल में 3 लाख, 40 हजार करोड़ का फायदा होगा। इसमें हैरानी की बात यह है कि जनता से महंगाई कम करने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार पेट्रो उत्पादों पर मोटा टैक्स वसूल रही है। 2014 के मई महीने के आंकड़ों का जिक्र करते हुए माकन ने कहा कि जब संप्रग ने सत्ता छोड़ी तो पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 9.48 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 3.56 रुपये प्रति लीटर थी। तब क्रूड ऑयल 107 डॉलर प्रति बैरल था।

आज क्रूड ऑयल 35 डॉलर प्रति बैरल है, तो पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क दोगुने से अधिक 22.98 रुपये प्रति लीटर है। इसी तरह डीजल पर 18.83 रुपये प्रति लीटर की दर से टैक्स वसूला जा रहा है। सरकार के इस रुख को जनविरोधी करार देते हुए माकन ने कहा कि सरकार इसी वजह से पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में नहीं ला रही। कांग्रेस पेट्रो उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने की मुखर आवाज उठा रही है, क्योंकि इसे कीमत घटेगी और आम लोगों को लाभ मिलेगा।

विश्वविद्यालयों को संबद्ध कॉलेजों का ब्योरा देना होगा जरूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- यूजीसी ने सभी केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों को दिए निर्देश
- संबद्धता को लेकर फैलाए जाने वाले भ्रम को देख उठाया कदम

कॉलेजों की संबद्धता को लेकर फैलाए जाने वाले भ्रम से छात्रों को बचाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक अहम पहल की है। इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों को अब अपने से संबद्ध कॉलेजों और संस्थानों का ब्योरा अनिवार्य रूप से वेबसाइट पर देना होगा। साथ ही यदि किसी कॉलेज की संबद्धता (एफिलेशन) खत्म की गई है तो इसकी भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा कॉलेजों को भी वेबसाइट पर यह बताना होगा कि उन्हें किस विश्वविद्यालय से किस विषय की किस अवधि तक के लिए संबद्धता दी गई है।

यूजीसी ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नया सत्र शुरू होने वाला है। जिसकी प्रक्रिया आने वाले दिनों में शुरू होने वाली है। ऐसे में छात्रों के मन में किसी संस्थान को लेकर कोई भी भ्रम की स्थिति पैदा न हो। देशभर के केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखे पत्र में यूजीसी ने कहा है कि उनकी जानकारी में ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं जिसमें यह पाया गया है कि विश्वविद्यालय अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर संबद्ध संस्थानों या कॉलेजों का ब्योरा अपडेट नहीं रखते हैं। इसके चलते कुछ संस्थान इसका फायदा उठाकर छात्रों को गलत जानकारी देते हैं।

यूजीसी ने इसके साथ ही विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर संबद्ध कॉलेजों की जानकारी नहीं मिलने के चलते सर्टीफिकेट के सत्यापन में देरी का मुद्दा भी उठाया है। इसके चलते छात्रों को नई नौकरियों को लेकर लंबा इंतजार करना पड़ता है क्योंकि सर्टीफिकेट को जांच के लिए विश्वविद्यालयों को ही भेजा जाता है, लेकिन संबद्धता खत्म हो जाने या नहीं होने के चलते उन्हें उसका जवाब समय पर नहीं मिल पाता। मालूम हो कि देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा समय में 900 से ज्यादा विश्वविद्यालय और 50 हजार से ज्यादा कॉलेज संचालित हैं।

संसदीय समिति ने कहा शोध के लिए डीआरडीओ में वैज्ञानिक अपर्याप्त

नई दिल्ली, आइएएनएस : एक संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में समर्पित शोध एवं विकास परियोजनाओं के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) में वैज्ञानिकों की संख्या को बेहद अपर्याप्त बताया है। डीआरडीओ के लिए अनुदान मांगों पर समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पांच साल में 131 वैज्ञानिक डीआरडीओ छोड़ चुके हैं। बजट में छह गुना से ज्यादा बढ़ोतरी के बावजूद 2001 से डीआरडीओ उतने ही कर्मचारियों से काम चला रहा है। वर्तमान में डीआरडीओ में वैज्ञानिकों के स्वीकृत पद 7,353 हैं, लेकिन 7,068 पर ही वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डीआरडीओ में कुल कर्मचारियों के 30 फीसद वैज्ञानिक हैं।

समिति के मुताबिक, 2010 में जनशक्ति योजना बोर्ड (एमपीबी) ने 4,966 कर्मचारी बढ़ाने की सिफारिश की थी। जबकि वित्त मंत्रालय ने 1,316 पदों की सिफारिश की थी। लेकिन यह मामला रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) के समक्ष लंबित है। एमपीबी की सिफारिश को 10 साल बीत जाने के बावजूद कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है। समिति ने रक्षा मंत्रालय से डीआरडीओ में वैज्ञानिकों के कुल स्वीकृत पदों का पुनर्निर्धारण करने और कैडर समीक्षा का प्रयास करने का अनुरोध किया है। साथ ही प्रथम चरण में वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 436 पदों के सीसीएस के समक्ष लंबित मामले में तेजी लाने का अनुरोध भी किया गया है। समिति का कहना है कि डीआरडीओ से ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए कुछ वित्तीय लाभों को भी रोक दिया गया है। इसके अलावा ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

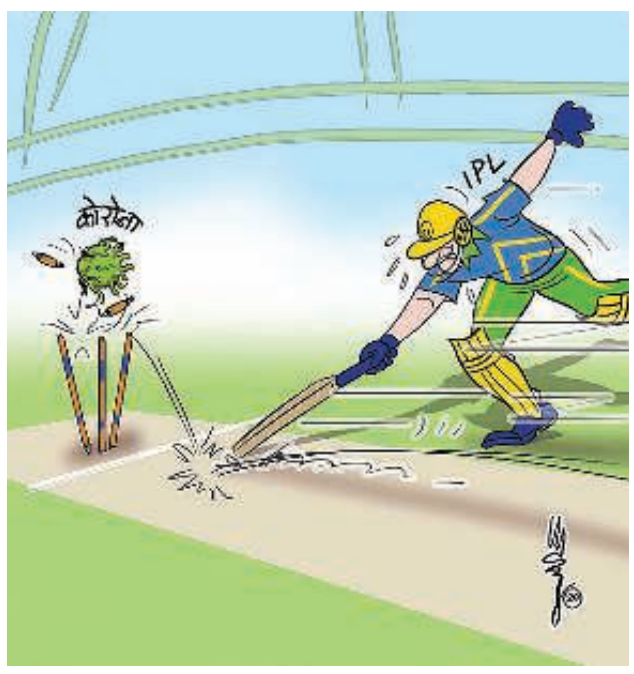

बोले शाह

2024 तक हर तीसरे लोकसभा क्षेत्र में होगा मेडिकल कॉलेज, सरकार का प्रयास, हर राज्य में की जाए एक एम्स की स्थापना

2030 तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में शीर्ष पर होगा भारत

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया में शीर्ष पर होगा। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक हर तीसरे लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान को गति दी जाए। इसके अलावा सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक राज्य में एक एम्स खोला जाए।

गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के दूसरे दीक्षा समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ की आबादी देश पर बोझ नहीं बल्कि ताकत है। चिकित्सा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 60 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। अब तक 91 लाख लोग इस योजना का लाभ भी पा चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए शाह ने कहा कि अटल जी ने देश को छह एम्स की सौगात दी थी। ऋषिकेश एम्स इन्हीं में से एक है। वर्तमान सरकार ने उनके सपने को आगे बढ़ाते हुए 16 और नए एम्स के साथ देश में 22 एम्स स्थापित करने का काम किया है। चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए देश में एमबीबीएस की 29 हजार और स्नातोकोत्तर में 17 हजार सीटें बढ़ाई गई हैं। उन्होंने युवा चिकित्सकों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने एम्स में प्रत्यारोपण खंड, नेत्र केंद्र, तंत्रिका विज्ञान केंद्र, कैंसर केंद्र, छात्रावास और प्रशासनिक खंड की नई योजनाओं का शिलान्यास भी किया।

ऋषिकेश में एम्स के दूसरे दीक्षा समारोह को संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने एम्स ऋषिकेश की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि एम्स ऋषिकेश तेजी से सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थानों में अपनी जगह बना रहा है। उन्होंने युवा चिकित्सकों से सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की अपील की।

252 विद्यार्थियों को मिली उपाधि : एम्स के दूसरे दीक्षा समारोह में कुल 252 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। इनमें एमबीबीएस 2013 बैच के 73, 2014 बैच के 92, एमडी एमएस के 14, बीएससी नर्सिंग के 57 व एमएससी नर्सिंग के 16 विद्यार्थी शामिल हैं।

REUNION IAS
IAS V.K.TRIPATHI PCS
"PENDRIVE COURSES"
कोरोना (CORONA) वायरस के कारण कक्षायें बाधित हुई है। अत: Pendrive के द्वारा घर बैठे अध्ययन करें।
(अध्ययन सामग्री तथा टेस्ट पेपर सहित)
GS-II + GS-IV (FULL COURSE)
राजनीति विज्ञान (OPT.)
(FULL COURSE)
राजव्यवस्था POLITY (PT)
B-11, 1st FLOOR, IN FRONT OF MEERUT SWEETS, MUKHERJEE NAGAR DELHI-9
9999421659-58